सरकार ने छोटे और मझोले उद्योगों की वित तक पहुंच आसान बनाई | उद्योग से जुड़े लोगों ने ऋण वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाने की मांग की

एमएसएमई के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है क्रेडिट कार्ड योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट कार्ड की शुरुआत एक परिवर्तनकारी कदम होने की उम्मीद है, जो वित्त तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि ऋण वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना होगा जिससे वित्तीय लाभों की व्यवसायों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

वित्तीय सहायता, डिजिटलीकरण और क्षेत्र-विशिष्ट पहलों पर जोर देने के लिए केंद्रीय बजट 2025 का एमएसएमई क्षेत्र ने व्यापक रूप से स्वागत किया है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करना है, जिनमें से प्रत्येक की सीमा पांच लाख रुपये है। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि यह कदम वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा और छोटे व्यवसायों के लिए तरलता की चुनौतियों को कम करेगा।

रिसर्जेंट इंडिया के प्रबंध निदेशक ज्योति प्रकाश गाडिया ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड पहल को ''गेम चेंजर'' कहा है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय पहुंच एक चुनौती बनी हुई है और यह कदम उनकी कार्यशील पूंजी की बाधाओं को काफी हद तक कम करेगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड की घोषणा उद्यम पोर्टल में पंजीकृत उद्यमों के लिए बहुत जरूरी वित्त की उपलब्धता के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इसके अतिरिक्त, बजट ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को पांच करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है। इस कदम से अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलने की उम्मीद है।

इन सकारात्मक कदमों के बावजूद उद्योग जगत का कहना है कि ऋण तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है। स्ट्रेटफिक्स कंसल्टिंग के सह-संस्थापक मुकुल गोयल ने ऋण वितरण प्रक्रिया में नौकरशाही बाधाओं को कम करने की आवश्यकता बताई है। गोयल ने कहा कि ये उपाय आशाजनक हैं, लेकिन एमएसएमई के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। समय पर और किफायती ऋण तक पहुँच कई छोटे व्यवसायों के लिए एक बाधा बनी हुई है।

****

10

लाख उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई को मिलेंगे यह कार्ड

05

पांच लाख रुपये होगी कार्ड की सीमा, आसानी से पैसा मिलेगा

मैन्यूफैक्चरिंग मिशन के लिए बनेगी कमेटी : गोयल

नई दिल्ली, प्रेट्र: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग मिशन के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति कारोबार करने की लागत में कटौती, भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करने व मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलाजी की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार करेगी। समिति में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह समिति उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेगी जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और जहां घरेलू व विदेशी दोनों बाजारों में मांग है और "हमें क्या करना चाहिए" पर सिफारिशें देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीति समर्थन, क्रियान्वयन रोडमैप, शासन और निगरानी ढांचा प्रदान करके "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करने वाले मिशन की घोषणा की है।